



NEERAJ®

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय

(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

IGNOU.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Ved Prakash Sharma



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय (Introduction to International Relations)

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1
Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1-3

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

खंड-1 : परिचय (Introduction)

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ	1
(Understanding International Relations)	
2. मूलभूत संकल्पनाएँ : राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन	13
और सामूहिक सुरक्षा के तत्त्व (Basic Concepts : Elements of National Power, National Interest, Collective Security, Balance of Power)	
3. वैश्विक व्यवस्था का विकास (विश्वयुद्ध II तक)	27
(Evolution of International System – Up to the World War-II)	

खंड-2 : दृष्टिकोण (Approaches)

4. यथार्थवाद	35
(Realism)	
5. सिस्टम (व्यवस्था) उपागम	45
(Systems Approach)	

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
-------	----------------------------	------

6.	निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory)	54
7.	रचनावाद (Constructivism)	63

खंड-3 : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाएँ (State and District Administration)

8.	शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण (Origins and Phases of the Cold War)	70
9.	शीत युद्ध का अंत और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव (End of the Cold War and its impact on International Relations)	82
10.	शक्ति के उभरते केन्द्र (Emergings Centres of Power)	92
11.	वैश्वीकरण (Globalisation)	102

खंड-4 : अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisations)

12.	संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्य (Role of Functions of United Nations)	113
13.	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन (International Economic Organisations)	122
14.	क्षेत्रवाद और नव-क्षेत्रवाद (Regionalism and New Regionalism)	136



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय
(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए किन्हीं दो उपागमों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-4, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 2

प्रश्न 2. द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-28, 'द्वितीय विश्व युद्ध' पृष्ठ-30, प्रश्न 3

प्रश्न 3. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-46, 'अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था उपागम'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(क) निर्भरता सिद्धांत में अवधारणाएँ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-57, प्रश्न 2

(ख) निर्भरता सिद्धांत में अवधारणाएँ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-66, प्रश्न 2

भाग-II

प्रश्न 5. शीतयुद्धोत्तर राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-85, प्रश्न 2

प्रश्न 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 3

प्रश्न 7. वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-107, प्रश्न 3

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-117, प्रश्न 4

(ख) विश्व बैंक की भूमिका

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-125, प्रश्न 2



QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय
(Introduction to International Relations)

B.P.S.C.-134

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्वों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-14, 'राष्ट्रीय हित की समझ'

प्रश्न 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 3

प्रश्न 3. परम्परागत यथार्थवाद के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-37, प्रश्न 2

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) द्विध्रुवीय प्रणाली

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-10, पृष्ठ-93, 'द्विध्रुवीय व्यवस्था'

(ख) यूरोपीय संघ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-124, 'यूरोपीय संघ'

भाग-II

प्रश्न 5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-115, 'संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का सुधार पर पुनर्गठन' तथा पृष्ठ-121, प्रश्न 3

प्रश्न 6. "बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दुनिया को एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता में स्थानांतरित करने के लिए परिस्थितियों की उत्पत्ति की।" चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-84, 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर नए परिप्रेक्ष्य का जन्म' तथा पृष्ठ-86, प्रश्न 3

प्रश्न 7. रचनावाद की दार्शनिक नींव की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-63, 'रचनावाद का दार्शनिक आधार'

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) ट्रस्टीशिप काउंसिल (Trusteeship Council)

उत्तर-ट्रस्टीशिप काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य संस्थानों में से एक, ट्रस्ट क्षेत्र के प्रशासन की निगरानी के लिए स्थापित किया

गया था, क्योंकि वे उपनिवेशों से संप्रभु राष्ट्रों में परिवर्तित हो गए थे। काउंसिल ने 1994 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, जब मूल 11 ट्रस्ट क्षेत्रों में से अंतिम ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।

चैंबर, जिसे मूल रूप से 1952 में वास्तुशिल्पी फिन जुहल द्वारा डिजाइन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र और डेनिश सरकार के बीच एसोसिएटेड डिजाइनर कैम्पर साल्टो और थॉमस सिग्मार्ड द्वारा मिलकर बनाया गया था।

न्यास परिषद के पांच सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं, इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गयी थी, जहां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-XII के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को सवर्धित करना बिना किसी भेदभाव के मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना है। मूल रूप में 11 न्यास प्रदेश थे। न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर, 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथक या पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। पलाऊ द्वीप समूह ऐसा अंतिम न्यास क्षेत्र था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त किये जाने के पश्चात् 1 नवंबर, 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिये। फिर भी, न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। हाल ही में, न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है।

(ख) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-124, 'विश्व व्यापार संगठन'



Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय (Introduction to International Relations)

खंड-1 : परिचय (Introduction)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ (Understanding International Relations)



परिचय

अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। साथ-ही-साथ संप्रभु राज्यों, अंतरसरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का भी अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक व्यापार प्रतिरूप एवं नेतृत्व क्षमता भी प्रभावित करती है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध सहायक सिद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना विश्व व्यवस्था के अनेक दृष्टिकोणों की तलाश और पेशकश करने में सहायता करता है। 1930 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ यथार्थवाद और उदारवाद की मुख्यधारा और सशक्त हुई है। इन दो दृष्टिकोणों को परंपरागत रूप से कूटनीतिक, सैन्य और रणनीतिक शक्तियों और उन्हें विस्तार देने के तरीकों के रूप में माना गया था। 1960 के दशक में व्यवहारवादियों और परंपरावादियों के मध्य बहस हुई, शक्तियों का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की कसौटी मानते हैं। 1970 और 1980 के दशक में तीसरी बहस उदारवादियों तथा यथार्थवादियों एवं मार्क्सवादियों के बीच थी। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक दृष्टि से समझते थे।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा वैचारिक ढांचा तैयार करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। इस अध्याय के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण, एक उपागम के रूप में उदारवाद, आलोचनात्मक उपागम तथा इन विविध सैद्धांतिक और अवधारणाओं की आलोचना आदि का अध्ययन करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

यथार्थवाद

यथार्थवाद अथवा राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है, जिसमें थ्यूसाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रणालियां हैं—यथार्थवाद, आदर्शवाद तथा नवयथार्थवाद। यथार्थवादियों का मत है कि सत्ता के लिए संघर्ष ही समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केन्द्रीय तत्त्व है। उनका यह मानना है कि राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य और द्वंद्व, किसी-न-किसी रूप में सदैव मौजूद रहते हैं, जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र-राज्यों की विदेश नीति को संचालित करता है। निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और यही द्वंद्व सीधा सत्ता-संघर्ष का परिणाम है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे वे हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं। अतः यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रों के मध्य सत्ता वितरण की व्याख्या करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र काम है।

हंस मोरगेंथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के छह सिद्धांतों को उजागर किया है, जो यह बताते हैं कि राज्य कैसे काम करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. राजनीति उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है, जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में निहित होती हैं।
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हित की अवधारणा की दृष्टि से परिभाषित किया जा सकता है।

2 / NEERAJ : अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय

3. राज्य शक्ति के प्रकार और प्रकृति समय, स्थान और संदर्भ में अलग होंगे, परंतु हित की संकल्पना सुसंगत रहती है।
4. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते हैं।
5. यथार्थवाद के अनुसार सभी चर एवं अचर वस्तुएं एक अवयव के रूप में हैं, जिसमें निरंतर प्रक्रिया हो रही है।
6. इसका राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है अर्थात् यह नीति किसी राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है?

नव-यथार्थवाद

नव-यथार्थवाद केनेथ वाल्ट्ज द्वारा अपनी पुस्तक 'थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स' में इसे यथार्थवाद के ही उन्नत विकास के रूप में प्रस्तुत किया था। वाल्ट्ज के नव-यथार्थवाद का मानना है कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझाने के रूप में लिया जाना चाहिए। संरचना को दो रूपों में परिभाषित किया गया है, प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का सिद्धांत, जो कि अराजकता लिए हुए है और द्वितीय, इकाइयों में क्षमता का वितरण।

संरचना एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मौजूदा अराजक व्यवस्था में हम पाते हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की रूचि दूसरे राष्ट्रों को अपेक्षित सामर्थ्य प्राप्त करने से रोकने में होती है।

इनका यह भी मानना है कि राष्ट्र-राज्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय समिति में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा इनका यह विचार है कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पहचान अराजकता व बहुकेन्द्रक गतिविधियों के रूप में की जा सकती है तथा इन गतिविधियों का स्रोत अब मात्र राज्य ही नहीं, अपितु गैर-राज्य तत्त्व भी है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक युद्ध, गृहयुद्ध की बढ़ती घटनाएं और प्रतिद्वंद्वी बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण यह जटिलता और भी जटिलतर हो गई है।

अतः नव-यथार्थवाद इस अराजक विश्व में सत्ता-संघर्ष के तत्त्व पर विशेष बल देता है। सत्ता-संघर्ष केवल राज्यों के बीच ही नहीं, अपितु उनमें से प्रत्येक के अन्दर भी है।

उदारवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उदारवादी सिद्धांतों का अग्रदूत आदर्शवाद था। आदर्शवाद जो स्वयं को यथार्थवादियों की आलोचना के रूप में देखता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद एक वैचारिक दृष्टिकोण है, जो यह मानता है कि एक राज्य को अपनी विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसे अपने आंतरिक राजनीतिक दर्शन में अपनाना चाहिए। विल्सन का आदर्शवाद उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के लिए एक अग्रदूत के रूप में था, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संस्था निर्माताओं के बीच पैदा हुआ।

उदारवाद यह मानता है कि राज्य की क्षमताओं के बजाय राज्य की प्राथमिकताएं, राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक

होती हैं। यथार्थवाद के विपरीत, जहां राज्य एक एकात्मक अभिनेता के रूप में देखा जाता है, वहीं उदारवाद राज्य के कार्यों में बहुलता के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार प्राथमिकताएं अलग-अलग राज्यों में उनकी संस्कृति, आर्थिक प्रणाली या सरकार के प्रकार के रूप में अलग-अलग कारकों पर निर्भर करेंगी। उदारवादी यह भी मानते हैं कि राज्यों के बीच संपर्क केवल राजनीतिक अथवा सुरक्षा के मामलों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इनमें आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामलों के लिए भी आपस में संपर्क होता रहता है, चाहे वह वाणिज्यिक कम्पनियों, संगठनों या व्यक्तियों के माध्यम से ही हो। इस प्रकार एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बावजूद सहयोग और सत्ता के व्यापक विचार के लिए बहुत से अवसर विद्यमान हैं।

1970 के दशक के बाद उदारवाद को नवउदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया गया था। उदारवाद के अंदर प्रमुख विषय हैं— (1) अन्योन्याश्रय उदारवाद, (2) लोकतांत्रिक उदारवाद तथा (3) उदार संस्थावाद।

आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य

1980 के दशक में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बल मिला। उन्होंने एक उत्तर-वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया, जो सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ता है। आलोचनात्मक सिद्धांत अनुकरणीय सिद्धांत है तथा वे उपेक्षित समूहों के उत्पीड़न को स्वतंत्रता की दिशा में काम करते हैं। प्रमुख आलोचनात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं—

मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत

मार्क्सवाद और नव-मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के संरचनावादी मानदण्ड हैं, जो यथार्थवादी और उदारवादियों के राज्य संघर्ष अथवा सहयोग के दृश्य को अस्वीकार करते हैं और इनके बजाय ये आर्थिक और भौतिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता का प्रमुख स्रोत पूंजीवादी वैश्वीकरण होगा, विशेष रूप से दो वर्गों के बीच संघर्ष, राष्ट्रीय पूंजीपति और महानगरीय सर्वहारा वर्ग। ऐतिहासिक भौतिकवाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में प्रक्रियाओं को समझने के लिए मार्क्सवाद की मार्गदर्शिका बने जा रहा था। इस प्रकार मार्क्स के लिए मानव इतिहास भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने और वर्ग संघर्ष और उस पर आधारित शोषण का विरोध करने के लिए एक संघर्ष रहा है। इसकी वैचारिक आलोचना के बावजूद मार्क्सवाद के पक्ष में मजबूत पक्ष और फायदे हैं। सर्वप्रथम इसका अन्याय और असमानता पर बल देना हर काल के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि मानव समाज की दो विफलताएं कभी अनुपस्थित नहीं रहेंगी। नव-यथार्थवाद की भांति मार्क्सवादी भी एक संरचनात्मक सिद्धांत है, लेकिन यह सैन्य-राजनीतिक ढांचे के बजाय आर्थिक

क्षेत्र पर केन्द्रित है। इसका विश्लेषण आधार और अधिरचना के बीच के संबंध को बताता है। संरचनात्मक प्रभावों का प्रोत अराजकता नहीं, अपितु उत्पादन का पूंजीवादी तरीका है, जो अन्यायपूर्ण राजनीतिक संस्थानों और राज्य संबंधों को परिभाषित करता है।

इस आर्थिक कमी को इस सिद्धांत का प्रमुख दोष भी माना जाता है। नव-ग्रामशीवादी स्कूल ने इसके समाधान में, एक और प्रस्ताव दिया। वैश्विक पूंजीवाद, राज्य संरचना और राजनीतिक-आर्थिक संस्थानों को मिलाकर, यह वैचारिक वर्चस्व का एक सिद्धांत बनाने में सफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में और बाहर सशक्त कुलीनों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से आधिपत्य स्थापित किया जाता है।

कालानुक्रमिक दृष्टिकोण से मार्क्सवाद ने समालोचनात्मक सिद्धांत के लिए नींव तैयार की और यह एंग्लो-अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोणों की समस्याएं सुलझाने में बेहतर साबित हुआ है। मार्क्सवाद का मानक नुकसान यह है कि यूरोपीय ज्ञानोदय के ब्रह्मांडवाद मूल्य से प्रेरित होने के कारण इसे यूरोकेन्द्रीय रूप में देखा जा सकता है।

निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है, जो यह तर्क देता है कि शक्ति की खोज में विकसित देश, राजनीतिक सलाहकारों, मिशनरियों, विशेषज्ञों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विकासशील देशों में उपयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में उन्हीं एकीकृत करते हैं। इससे एक आर्थिक पैटर्न प्रकट होता है, जहां विकासशील देश कच्चा माल निर्यात करके संसाधित माल आयात करते हैं, जिससे वे विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं।

यथार्थवादी और उदारवादी दोनों ही इस सिद्धांत को राजनीति से प्रेरित मानते हैं और कहते हैं कि इसका दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण और पक्षपाती है। उत्तर-प्रत्यक्षवादी इस मान्यता से असहमत हैं कि वर्ग संघर्ष मानव जीवन का सबसे प्रमुख भाग है, जिसके आधार पर संपूर्ण मानव इतिहास और व्यवहार समझा जा सकता है।

नारीवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण 1960 के दशक में यूरोप में प्रकट हुआ, जहां महिलाओं ने विचार प्रकट किया कि वे जीव विज्ञान में अंतर के कारण अधीनस्थ हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को चुनौती दी और इस बात पर बल दिया कि ये भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि महिलाओं के अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से बाहर रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादियों का मानना है कि लिंग संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिन्न अंग हैं। अतः राजनयिक महिलाओं और वैवाहिक संबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नारीवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जेंडर विवेक शून्य होने का आरोप लगाया। यह महिलाओं की आवाज और विचारों को

शामिल नहीं करता। राज्य की नीति निर्यात आय, आर्थिक विषयों और तुलनात्मक श्रम लागत के घटकों पर संचालित होती है, परंतु राज्य ने सामाजिक सेवाओं के वितरण, पूर्ण रोजगार के प्रावधान, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।

नारीवाद के अंदर कई तत्व हैं, जो महिलाओं को अपने अंतर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदार नारीवादी समान राजनीतिक अधिकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में समानता पर बल देते हैं, जबकि समाजवादी नारीवादी सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने और महिलाओं की मुक्ति के बारे में बात करते हैं।

उत्तर-संरचनावाद

उत्तर-संरचनावाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे ज्यादातर दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि यह स्वयं को एक ऐसे सिद्धांत, स्कूल या प्रतिमान के रूप में नहीं देखता है, जो कि केवल किसी एक ही विषय के बारे में लेखा-जोखा रखता है। इसके बजाय उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण एक लोकाचार, तरीका और दृष्टिकोण है, जो विशेष रूप से आलोचनाओं की जांच एवं खोज करता है। उत्तर-संरचनावाद आलोचना को एक स्वाभाविक सकारात्मक तरीके से देखता है, जो कि विकल्पों की खोज के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है।

हरित राजनीति

हरित राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों का एक उप-क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग से संबंधित है। 1970 के दशक के बाद से यह पर्यावरणीय नीतिगत चर्चा में पर्यावरण का एक प्रमुख कारक बन गया। 1990 के दशक में इसने जलवायु परिवर्तन की चिंता के साथ और ज्यादा संकर्षण हासिल किया। यह सिद्धांत मानव जाति और प्रकृति के मध्य एक कड़ी की व्याख्या करता है। हरित राजनीति सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की जरूरत पर बल देता है। इस सिद्धांत का मानना है कि उन्नति और विकास केवल तभी स्थिर रह सकता है, जब यह पर्यावरण के साथ मेल खाता हो।

सामाजिक रचनावाद

सामाजिक रचनावाद या रचनावाद नव उदारवादी तथा नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के समक्ष एक चुनौती के रूप में वर्णित किया जाता है। माइकल बर्नेट वर्णन करते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। यह संरचना कैसे राज्यों के हितों तथा उनकी पहचान को परिभाषित करती है। राज्य और गैर-राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक रचनावाद के प्रमुख सिद्धांत का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होती है। सामाजिक रचनावाद का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता सामाजिक रूप से ज्ञानात्मक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है। यह सिद्धांत

4 / NEERAJ : अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के उत्पादन में सिद्धांतों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक बहस के रूप में प्रकट हुआ है।

उत्तर-उपनिवेशवाद

उत्तर-उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण में मुख्यधारा का क्षेत्र नहीं माना जाता है। उत्तर-उपनिवेशवाद विश्व राजनीति में औपनिवेशिक स्थिरता की शक्ति और नस्लवाद के अस्तित्व को जारी रखने पर बल देता है।

उत्तर-उपनिवेशवाद का उदय 1919-1945 में माना जाता है, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् ही उच्च शिखर पर पहुँचा। उत्तर-उपनिवेशवाद यह विचार प्रकट करता है कि पाश्चात्य जगत किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। वह बताता है कि 'श्वेत व्यक्ति का बोझ' सिद्धांत ढोंग है और यह अल्पविकसित और विकासशील देशों को पाश्चात्य प्रभुत्व का अधीनस्थ बनाए रखने का एक तरीका है।

उत्तर-उपनिवेशवाद के आलोचकों का मानना है कि पाश्चात्य विचारों को छोड़कर उत्तर-उपनिवेशवादियों ने परंपरागत मूल्यों और अधिकार संरचनाओं के स्थान पर प्रगतिशील राजनीति को छोड़ दिया है। नारीवादियों का मानना है कि पाश्चात्य विचारों को छोड़ना उनके आंदोलन की उन्नति में रुकावट है क्योंकि ज्यादातर स्वदेशी संस्कृति महिलाओं के अधिकारों को दबाती है।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. यथार्थवाद की अवधारणा को समझाइए।

उत्तर—यथार्थवाद के लिए अंग्रेजी का शब्द 'रियलिज्म' है। 'रियल' शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु। अतः रियल का अर्थ होता है वस्तु संबंधी। यही कारण है कि यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व से संबंधित एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य है और प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अनुभव हमें इन्द्रियों से होता है। वास्तव में यथार्थवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। वस्तु को वास्तविक अथवा यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तववाद या यथार्थवाद की संज्ञा दी गई है। यथार्थवाद संसार को मिथ्या कहने वाली भावना का विरोधी स्वर है।

यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है, जिसमें थ्यूसाइड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रणालियाँ हैं—यथार्थवाद, आदर्शवाद तथा नवयथार्थवाद। यथार्थवादियों का मत है कि सत्ता के लिए संघर्ष ही समस्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का

केन्द्रीय तत्त्व है। उनका यह मानना है कि राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य और द्वंद्व, किसी-न-किसी रूप में सदैव मौजूद रहते हैं, जिस प्रकार निजी हित वैयक्तिक आचरण को संचालित करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित राष्ट्र-राज्यों की विदेश नीति को संचालित करता है। निरंतर द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है और यही द्वंद्व सीधा सत्ता-संघर्ष का परिणाम है। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे वे हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं। अतः यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रों के मध्य सत्ता वितरण की व्याख्या करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र काम है।

यथार्थवादियों का मानना है कि राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता होते हैं। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केन्द्रित सिद्धांत है। यह विचार उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ विरोधाभास प्रकट करता है, जो गैर-राज्य अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में समायोजित करता है।

यथार्थवादियों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है, जिसका अर्थ है कि वहाँ केन्द्रीय सत्ता नहीं है, जो राष्ट्र राज्यों में सामंजस्य रख सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए राज्यों की सहायता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए।

अतः यथार्थवाद में अनेक मान्यताएँ हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र-राज्य इस अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऐकिक व भौगोलिक आधारित हैं, जहाँ कोई भी वास्तविक आधिकारिक विश्व सरकार के रूप में मौजूद नहीं है, जो इन राष्ट्र-राज्यों के मध्य अन्तःक्रिया या सहभागिताओं को विनियमित करने में सक्षम हो। दूसरे, यह अंतरसरकारी संगठनों (IGOs), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (MNCs) के बजाय संप्रभु राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। इस प्रकार राज्य ही सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। ऐसे में एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ अपने स्वयं के स्वार्थ की खोज में एक तर्कसंगत स्वायत्त अभिनेता के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है।

प्रश्न 2. उदारवाद क्या है? उदारवाद के प्रमुख विषयों की व्याख्या करें।

उत्तर—अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद वह विचारधारा है, जिसके तहत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं की सृष्टिवृद्ध और सामूहिक प्रयास का परिणाम माना जाता है। स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति इसके प्रमुख